

**भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA**वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

18 जनवरी 2024

आरबीआई बुलेटिन - जनवरी 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपने मासिक बुलेटिन का जनवरी 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में सात भाषण, छह आलेख, वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2023 और बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2022-23, जनवरी 2024 बुलेटिन के अनुपूरक हैं।

छह आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. क्या खाद्य कीमतें भारत की मुद्रास्फीति का 'वास्तविक' मूल कारण हैं?; III. खुदरा क्षेत्र में ऋण वृद्धि की गतिकी: जोखिम और स्थिरता संबंधी चिंताएं; IV. स्टॉक-बॉण्ड सहसंबंध और समष्टि अर्थव्यवस्था: भारत से साक्ष्य; V. कृषि आपूर्ति शृंखला गतिकी: अखिल भारतीय सर्वेक्षण से साक्ष्य; और VI. जलवायु दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण: अनिश्चितताओं में संचालन।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

विश्व अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में संवृद्धि की विभिन्न संभावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एशिया के नेतृत्व वाली उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं, शेष विश्व से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में आशा से अधिक मजबूत संवृद्धि दर्ज की, जो उपभोग से निवेश की ओर बदलाव पर आधारित है। पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर निजी निवेश को बढ़ावा देने लगा है। प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण दिसंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

II. क्या खाद्य कीमतें भारत की मुद्रास्फीति का 'वास्तविक' मूल कारण हैं?

माइकल देवव्रत पात्र, जॉइस जॉन और आशीष थॉमस जॉर्ज द्वारा

भारत में लंबे समय से बढ़ी हुई खाद्य कीमतों के हालिया अनुभव के संदर्भ में, यह पेपर मौद्रिक नीति के लिए इसके निहितार्थ को समझने के लिए खाद्य मुद्रास्फीति के मूल गुणों, अर्थात् अस्थिरता, दृढ़ता, प्रभाव विस्तार और चक्रीय संवेदनशीलता की जांच करता है।

मुख्य बातें:

- खाद्य कीमतों में बड़े और लगातार बदलाव से हेडलाइन मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से प्रभावित करने की क्षमता है, क्योंकि खाद्य समूह के कुछ घटकों की कीमतें मूल मुद्रास्फीति गुणों को संतुष्ट करने के लिए देखी जाती हैं।

- नीति निर्माताओं को क्षणिक आघातों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करने के जोखिमों को कम करने के साथ-साथ लगातार आने वाले आघातों से निपटने के लिए खाद्य मूल्य के आघातों के स्रोतों और प्रकृति को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

III. खुदरा क्षेत्र में ऋण वृद्धि की गतिकी: जोखिम और स्थिरता संबंधी चिंताएं

विजय सिंह शेखावत, अवधेश कुमार शुक्ला, एसवी सुब्रह्मण्यम और जुगनू अंसारी द्वारा

यह आलेख पर्यवेक्षी डेटा का उपयोग करके अंतर-अस्थायी आधार पर पर्यवेक्षित संस्थाओं में खुदरा ऋण प्रवाह और आस्ति गुणवत्ता की गतिकी का विश्लेषण करता है। यह आलेख खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में जोखिम की गतिकी का विस्तृत स्तर पर विश्लेषण करने के लिए क्रेडिट ब्यूरो के डेटा का भी उपयोग करता है।

मुख्य बातें:

- खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के महामारी के बाद के व्यवहार में संवृद्धि और जोखिम मापदंडों दोनों के संदर्भ में सुधार हुआ है। अनुभवजन्य परीक्षण खुदरा ऋण क्षेत्रों में व्यापक संवृद्धि के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत देते हैं।
- ऋण प्रवाह में हालिया वृद्धि के परिणामस्वरूप खुदरा ऋण खंड में दबाव उत्पन्न हुआ है, तथापि अरक्षित क्षेत्र में कतिपय उप-खंड कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, जिससे वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।
- चूँकि पर्यवेक्षित संस्थाएँ तेजी से खुदरा ऋण पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए पूर्व-निवारक समष्टि विवेकपूर्ण उपाय प्रणालीगत और संस्था-स्तर दोनों पर वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा संकेत हैं।
- नीति निर्माता संरचनात्मक विवेकपूर्ण उपकरणों, यथा खुदरा उधारकर्ताओं का ऋण-सेवा अनुपात और ऋण-से-आय अनुपात का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं। नीति निर्माता उधारकर्ताओं से अपेक्षित सहमति प्राप्त करने के लिए; ऋण हामीदारी को मजबूत करने; और मॉडलों की निगरानी को मजबूत करने के लिए उभरते प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात् खाता एग्रीगेटर्स का उपयोग करने के लिए उधारदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तरह के ढांचे समग्र रूप से उधारकर्ता के लीवरेज की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं। कतिपय उधारकर्ताओं या उत्पाद श्रेणियों के लिए ऋण-से-आय (डीटीआई) सीमा निर्धारित करके इसे और बढ़ाया जा सकता है। ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात पर प्रतिबंध के साथ-साथ डीटीआई सीमाएं प्रभावी समष्टि विवेकपूर्ण उपकरण हैं, जिन्हें प्रणालीगत जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए समकालीन (सिंक्रोनाइज़) किया जा सकता है। साथ ही, ऐसे समष्टि विवेकपूर्ण उपकरणों को ऋण संवृद्धि को सहारा देने या कम करने के लिए उभरती समष्टि-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शीघ्रता से समायोजित किया जा सकता है।

IV. स्टॉक-बॉण्ड सहसंबंध और समष्टि अर्थव्यवस्था: भारत से साक्ष्य

अमित पवार, मयंक गुप्ता, पलक गोदारा और सुब्रत कुमार सीत द्वारा

यह अध्ययन अप्रैल 2004 से अगस्त 2023 तक भारत में विभिन्न मुद्रास्फीति और उत्पादन व्यवस्थाओं के अंतर्गत समयांतर स्टॉक-बॉण्ड सहसंबंध की जांच करता है।

मुख्य बातें:

- यह देखा गया है कि भारत में सकारात्मक स्टॉक-बॉण्ड सहसंबंध की कड़ियों (एपिसोड) की तुलना में नकारात्मक स्टॉक-बॉण्ड सहसंबंध की अवधि अल्पकालिक है जो बॉण्ड और इक्विटी के बीच न्यूनतर विविधीकरण लाभों को रेखांकित करती है। तथापि, इक्विटी पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने के लिए बॉण्ड एक उपयोगी वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- सुरक्षा हेतु वित्तीय बाजारों में जोखिम से बचने के कारण सहसंबंध सकारात्मक से नकारात्मक संकेत में बदल सकता है।
- परिणाम बताते हैं कि जब मुद्रास्फीति कम होती है, और अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है, तो निवेशकों द्वारा स्टॉक और बॉण्ड दोनों खरीदने की अधिक संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक स्टॉक बॉण्ड सहसंबंध होता है।

V. कृषि आपूर्ति श्रृंखला गतिकी: अखिल भारतीय सर्वेक्षण से साक्ष्य

डी. सुगंथी, ऋषभ कुमार और मोनिका सेठी द्वारा

यह आलेख किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से कृषि आपूर्ति श्रृंखला की गतिकी की जांच करता है। 15 खरीफ फसलों को शामिल करने वाला सर्वेक्षण दिसंबर 2022-फरवरी 2023 के दौरान चुनिंदा उत्पादन (चयनित वस्तुओं के प्राथमिक उत्पादक केंद्र) और उपभोग केंद्रों (प्रमुख शहरों) में किया गया था।

मुख्य बातें:

- सर्वेक्षण से पता चलता है कि उपभोक्ता कीमतों में किसानों की औसत हिस्सेदारी विभिन्न फसलों में 33 से 70 प्रतिशत तक है, जिसमें खराब होने वाली वस्तुओं में किसानों की हिस्सेदारी औसतन कम है।
- खुदरा स्तर पर देखे गए मार्क-अप आम तौर पर व्यापारियों की तुलना में अधिक थे, यह दर्शाता है कि विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के संबंध में, आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद हानि, खूँटे (वैज) (खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं की मूल्य वृद्धि के बीच का अंतर) में योगदान करती है।
- सर्वेक्षण उत्तरदाताओं के अनुसार, मंडियों में लेनदेन के लिए नकदी भुगतान का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में, इसका उपयोग व्यापारियों के बीच सबसे अधिक था, उसके बाद खुदरा विक्रेताओं का स्थान था। 2018 सर्वेक्षण के सापेक्ष व्यापारियों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के उपयोग में 3 गुना से अधिक और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई।
- व्यापारियों के अनुसार, मंडियों में गुणवत्ता मूल्यांकन की सुविधा उन्हें लाभान्वित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीति थी, इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद और ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-एनएएम) रही। उनके विचार में, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कमोडिटी वायदा व्यापार और स्टॉकिंग सीमा में ढील से कृषि विपणन में सुधार होगा।
- अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि जिला स्तर पर कृषि बाज़ार की सघनता बढ़ने से बढ़ी हुई स्थानिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से व्यापारियों के मूल्य बढ़ाने में कमी आती है।

- कुल मिलाकर, सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि कृषि बाजारों, गोदामों, पूर्व-प्रसंस्करण सुविधाओं, परिपक्व इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज का और विकास महत्वपूर्ण है। इनसे प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिलेगी और आपूर्ति श्रृंखला में बर्बादी भी कम होगी। ये उपाय हाल के वर्षों में देखी गई खाद्य कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को रोकने में भी मदद कर सकते हैं।

VI. जलवायु दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण: अनिश्चितताओं में संचालन

अमित सिन्हा और शिवांग भनवडिया द्वारा

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को वित्तीय संस्थाओं के लिए उभरते जोखिमों के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। यह आलेख वित्तीय संस्थानों पर जलवायु जोखिम के प्रभाव को मापने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित पायलट जलवायु असुरक्षितता मूल्यांकन और दबाव परीक्षण (वीएएसटी) अभ्यास के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और निष्कर्षों का विवरण देता है। यह अभ्यास प्रकृति में खोजपूर्ण था और इसमें कोई विनियामक या पर्यवेक्षी निहितार्थ नहीं था।

मुख्य बातें:

- अभ्यास में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बैंक जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रति असुरक्षित हैं और उन्हें जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और प्रबंधन करने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- वीएएसटी अभ्यास से पता चला कि विभिन्न परिदृश्यों में जलवायु संबंधी जोखिमों के कारण सहभागी बैंकों की ऋण हानि की संभावना¹ में वृद्धि होगी।
- जलवायु खतरों के परिदृश्य विश्लेषण और मॉडलिंग में शामिल जटिलताओं के साथ-साथ अपेक्षित डेटा की कमी के कारण, जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पहल प्रारंभिक चरण में हैं। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि बैंक और अन्य हितधारक इस बात पर सहमत हैं कि जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और प्रबंधन करने और आगामी वर्षों में सूचित नीति निर्माण की सुविधा के लिए ऐसी पहलों को परिष्कृत और समय-समय पर अद्यतित किया जाना चाहिए।

बुलेटिन के आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(योगेश दयाल)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1695

मुख्य महाप्रबंधक

¹ ऋण हानि की संभावना सकल निधि-आधारित एक्सपोज़र के उत्पाद, डिफॉल्ट की संभावना और डिफॉल्ट के कारण होने वाली हानि को इंगित करती है।